Need to grant more time to footwear industry to adhere to new BIS norms and address the concerns of footwear manufacturers- laid

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): देश में जूते-चप्पलों के व्यवसायी मेक इन इंडिया की सरकारी पहल का समर्थन करते हैं। फुटवियर क्षेत्र के भीतर कई चिंताएं हैं बी.आई.एस. के कार्यान्वयन से पहले फुट वियर के इनहाउस परीक्षण के लिए क्लस्टर आधारित फुट वियर लैब स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान करने के साथ सभी के लिए एक ही लाइसेंस दिया जाना चाहिए। भले ही फैक्ट्री अलग-अलग प्रकार के जूते बनाती हो। बी.आई.एस से पहले के पुराने स्टॉक को वापस नहीं किया जाय और खुदरा क्षेत्र के साथ चर्चा के बाद उसे निपटाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाय। जूते बनाने से पहले बी.आई.एस. के तहत जूते बनाने में आवश्यक अधिक घटकों को प्राप्त किया जाय ताकि जूते की गुणवत्ता पूरी तरह बनी रहे। इसके लागू होने के बाद 3 साल तक कोई ऑडिट न हो। परीक्षण मानकों को बदलकर SATRA मानकों के अनुसार होना चाहिए। जूते की परीक्षण लागत बहुत मामूली और सब्सिडी युक्त होनी चाहिए ताकि यह सबसे छोटे क्षेत्र के लिए संभव हो। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन विषयों की ओर ध्यान दे और समस्या का निराकरण करें।